खंड 19 नंबर 4 अक्टूबर 2023

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट का समापन

जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट का समापन कार्यक्रम 26 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में बेहद उत्साहपूर्ण ढंग से आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम के साथ ही देश के कोने–कोने में स्थित विश्वविद्यालयों में जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे व्याख्यानों का भी भव्य समापन हो गया।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से इस प्रतिष्ठित अवसर की शोभा बढ़ाई और विश्वविद्यालयों के 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित किया, जो अपने कुलपतियों और शिक्षकों सहित आयोजन स्थल पर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में विद्यार्थी आभासी रूप से भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मुख्य समन्वयक, जी–20 भारत, श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला ने स्वागत भाषण दिया।

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

यहां श्री अपूर्व चंद्रा; सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सुश्री मीता लोचन; सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग, श्री मुक्तेश परदेशी; विशेष सचिव (जी–20 परिचालन), श्री अभय ठाकुर; अपर सचिव, जी–20 सचिवालय और प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार; अध्यक्ष, यूजीसी सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के बीच पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इस पैनल चर्चा का संचालन आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने किया। इसमें भारत की जी–20 की अध्यक्षता और नई दिल्ली, भारत में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख तत्वों की रूपरेखा पर विचार–विमर्श किया गया।

इस दिलचस्प चर्चा के बाद 'धरती कहे पुकार के' नामक नाटक के रूप में एक सांस्कृतिक प्रस्तुति का आयोजन किया गया। 'धरती माता के गुणगान' के थीम पर आधारित इस प्रस्तुति के गूढ़ संदेश में पृथ्वी के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी के आह्वान को प्रतिध्वनित किया गया।

जी–20 भारत के शेरपा श्री अमिताभ कांत ने अपने संबोधन में भारत की जी–20 अध्यक्षता की सफलता पर बल देते हुए वैश्विक प्राथ. मिकता के प्रमुख मुद्दों पर सर्वसम्मति कायम होने से संबंधित यात्रा के बारे में चर्चा की। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने जी–20 की भारत की अध्यक्षता के लिए भारतीय नेतृत्व के विजन और इसके समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विचारों के त्रुटिहीन प्रसार की पुष्टि की। उन्होंने भारत की जी–20 की अध्यक्षता को भविष्य में अनुसंधान और विश्लेषण की केस स्टडी के रूप विकसित किए जाने के महत्व पर बल दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत की जी–20 की अध्यक्षता की सफलता भावी पीढ़ियों के लिए और भी ज्यादा समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान देगी। इस अवसर पर भारत के शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान भी उपस्थित थे। उन्होंने वैश्विक भू–राजनीतिक और आर्थिक उथल–पुथल की पृष्ठभूमि में सर्वसम्मति कायम करने और दूरदर्शितापूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र तैयार करने की दिशा में भारत के प्रयासों के लिए बधाई दी।

आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंच की शोभा बढ़ाते हुए उपस्थित विद्या. र्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने भारत के सफल चंद्रयान मिशन और सौर मिशन के प्रक्षेपण को याद करते हुए चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और नए सदस्यों को शामिल किए जाने, जी–20 नेताओं के नई दिल्ली घोषणा पत्र, जिस पर चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में सभी सदस्य देशों में सर्वसम्मति कायम होने, अफ्रीकी संघ को जी–20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने, भारत के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन और भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में चर्चा की।

उन्होंने युवाओं से सीधे संवाद करते हुए कहा कि आशावादिता, अवसर और खुलेपन से देश के युवाओं की प्रगति होगी। उन्होंने युवाओं से 1 अक्टूबर 2023 को देश भर में आयोजित होने वाले व्यापक स्वच्छता अभियान में भाग लेने, डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने और उसका हिस्सा बनने तथा 'वोकल फॉर लोकल' मुहिम को सक्रिय समर्थन देने की अपील की। उन्होंने भारत के युवाओं को प्रेरित करने और विभिन्न आया. जन–पूर्व गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल की सराहना की।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चार प्रकाशनों का भी विमोचन किया ; द ग्रैंड सक्सेस ऑफ जी–20 भारत प्रेसीडेंसी : विज़नरी लीडरशिप, इंडियाज जी–20 प्रेसीडेंसी : वसुधैव कुटुंबकम्; कंपेडियम ऑफ जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम; और शोकेसिंग इंडियन कल्चर ऐट जी–20।

कुछ झलकियां

ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में सीएमईसी

ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के दौरान प्रतिभागी

आरआईएस में समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी) बेहद महत्वपूर्ण ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023 में ज्ञान भागीदार था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इसका आयोजन 17–19 अक्टूबर 2023 को एमएमआरडीए ग्राउंड, मुंबई में किया गया।

महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, और माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सीएमईसी के प्रकाशन, "प्रोपेलिंग इंडियाज़ मैरीटाइम विज़नः इम्पैक्ट ऑफ़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़" का विमोचन किया। ज्ञान भागीदार के रूप में सीएमईसी ने जीएमआईएस 2023 के प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय गोलमेज सत्र के लिए चर्चा के व्यापक विषयों में योगदान देने के अलावा, पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करने में भी अपार योगदान दिया। सीएमईसी ने चार गोलमेज सत्र, ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर (जीईसी), यूरोप, अफ्रीका और हिंद प्रशांत का भी आयोजन किया।

उद्घाटन के ऐन बाद जीएमआईएस 2023 में 17 अक्टूबर को वैश्विक आर्थिक गलियारे पर सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने की और इसका संचालन आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने किया। गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 33 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और 17 भारतीय कंपनियों के सीईओ शामिल थे।

इस दौरान चर्चाएं गलियारे की अवधारणा और समावेशी एवं सतत विकास पर उनके संभावित प्रभाव पर केंद्रित रहीं। इस संदर्भ में, प्रस्तावित भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को यात्रा में लगने वाले कम समय के कारण वित्त जुटाने और पर्यावरण में सहायता करने के संदर्भ में आशाजनक स्थायी समाधानों के रूप में देखा गया। गलियारों के दायरे में आने वाले देशों के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं और नए शिपिंग मार्गों की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया। हिंद–प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ), भारत–म्यांमार–थाईलैंड और एशिया–अफ्रीका विकास गलियारे जैसी उल्लेखनीय पहलों का भी इस संदर्भ में उल्लेख किया गया कि उन्होंने किस प्रकार मूल्य–आधारित आर्थिक ढांचे का निर्माण किया है।

दुनिया भर के वक्ताओं ने अपने गहन अनुभव साझा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लघु–समुद्री परिवहन में सुधार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जो पश्चिमी यूरोप के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आर्थिक गलियारों के प्रति भ. ारत के सक्रिय दृष्टिकोण और आईएमईसी के महत्व को रेखांकित किया। सामान्य धारणा यह थी कि प्रतिभागी देशों के बीच विश्वास, राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक प्रयास शुरू करने के लिए ठोस समझौते करने का आधार होगा।

18 अक्टूबर 2023 को यूरोप पर सत्र आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी ने की और इसका संचालन सीएमईसी के परामर्शदाता श्री अमितेंदु पालित ने किया। यूरोपीय समुद्री देशों के नियामकों से संबंधि ात वक्ताओं ने भारत के समुद्री और शिपिंग सरोकारों और इन्हें यूरोप के निवेश अनुमानों के साथ संबद्ध किए जाने पर गौर किया। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री संजय वर्मा ने आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा नि. हितार्थों का उल्लेख कर समुद्री कनेक्टिविटी के बहुआयामी पहलुओं पर जोर देते हुए बढ़ते भारत–नॉर्डिक संबंधों और यूरोपीय संघ के साथ फासले मिटाने के महत्व को भी रेखांकित किया। डेनिश मैरीटाइम अथॉरिटी के महानिदेशक श्री एंड्रियास नॉर्डसेथ ने ग्रीन शिपिंग की चुनौतियों और अवसरों तथा स्वच्छ, डीकार्बोनाइज्ड शिपिंग प्रथाओं की ओर रुख करने की बात करते हुए इस हरित रूपांतरण या ग्रीन ट्रांजिशन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। इस रूपांतरण की दिशा में सहयोग, अंतरराष्ट्रीय नियम और कुशल कार्यबल को महत्वपूर्ण ा माना गया।

सुश्री ब्रिगिट गिज्सबर्स डीजी, एविएशन एंड मैरीटाइम अफेयर्स, नीदरलैंड ने भारत और नीदरलैंड के बीच समझौता ज्ञापनों

और सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए ग्रीन शिपिंग, स्मार्ट बंदरगाहों और क्षमता निर्माण की अहमियत पर बल दिया। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव श्री राजेश सिन्हा ने जहाज पुनर्चक्रण और संबंधित मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ को भी भारतीय हितों को पहचानने की आवश्यकता है। अन्य वक्ताओं ने डिजिटलीकरण, स्थिरता, सुरक्षा और ग्रीन बंदरगाहों जैसे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। बढ़ते भारत–यूरोपीय संघ व्यापार के परिणामस्वरूप शिपिंग क्षमताओं में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले प्रमुख अवसरों पर भी गौर किया गया, क्योंकि उन्हें उचित क्रॉस–कंट्री नियमों और मानकों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता होगी।

जीएमआईएस 2023 में 19 अक्टूबर को आयोजित हिंद–प्रशांत सत्र की अध्यक्षता माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने की और इसका संचालन सीएमईसी समन्वयक श्री सुभोमोय भट्टाचार्जी ने किया। श्री ठाकुर ने इस बात को रेखांकित किया कि प्रशांत महासागर एक महत्वपूर्ण वैश्विक नेविगेशन क्षेत्र है, जिसमें सतत विकास और न्यायसंगत विकास की संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री सहयोग पर भरोसा करते हुए विविधीकरण और अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर जोर देता है। आईपीईएफ और आईपीएमडीए जैसी पहल स्वच्छ, निष्पक्ष अर्थव्यवस्थाओं और सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए आर्थिक केंद्रीकरण से दूर रहने की आवश्यकता बताई। ये उपाय अधिक विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाएंगे। इसलिए हिंद– प्रशांत में उठाए गए कदम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण होंगे, जिनके लिए देशों के बीच समुद्री सहयोग आवश्यक है। सत्र में सम्मिलित होने वाले सम्मानित अतिथि वक्ताओं में महामहिम श्री नारेक तेरियन उप अर्थव्यवस्था मंत्री, आर्मे. निया, महामहिम श्री जेपबारोव रोवशेन उप प्रमुख "तुर्कमेनडेनिज़डेरायोलरी", तुर्कमेनिस्. तान और श्रीलंका के पत्तन, पोत परिवहन और विमानन मंत्री श्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा, शामिल थे। सत्र में सीमा पार सहयोग बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया गया, क्षेत्रीय विकास

जीएमआईएस में विशिष्ट गणमान्य हस्तियां

को प्रेरित करने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया और हिंद–प्रशांत का विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर जोर दिया गया। श्री पी. कुमारन, ओएसडी (ईआर एंड डीपीए), विदेश मंत्रालय ने इस विशाल महासागर के दोनों तरफ के देशों के हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पास अपने समुद्री व्यापार का दायरा बढ़ाने जैसे अवसर हैं लेकिन उन्हें टिकाऊ प्रौद्योगिकी अपनाने और ग्रीन शिपिंग का रुख करने जैसी नई चुनौतियों से भी अवगत रहना होगा।

जीएमआईएस 2023 में अफ्रीका गोलमेज सम्मेलन 19 अक्टूबर को माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसका संचालन सीएमईसी समन्वयक श्री सुभोमोय भट्टाचार्जी ने किया। इसमें कोमोरोस के माननीय क्षेत्रीय योजना, शहरी विकास, भूमि कार्य और भूतल पि. रवहन मंत्री महामहिम श्री अफ्रेटेन यूसुफ़ा मदजॉइनी और ज़ांज़ीबार, तंजानिया में नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य पालन मंत्री महामहिम श्री सुलेमान मसूद मकामे जैसे प्रमुख अतिथियों ने अपने अनुभव साझा किए। सत्र के संयोजक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष श्री संजय सेठी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बंदरगाह सीमा पार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की कुंजी हैं। उन्होंने नीली अर्थव्यवस्था के महत्व पर भी चर्चा की।

सत्र के दौरान चर्चा संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता, विकास के नए अवसरों के सृजन और बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग के आवश्यक पहलूओं पर केंद्रित रही। इस संदर्भ में, तंजानिया और भारत के बीच इस क्षेत्र में हाल ही में हस्ताक्षरित समझौतों की सराहना की गई।

सत्र में बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियों, समुद्री परिवहन, मछली पकड़ने और पर्यटन के महत्व को रेखांकित करने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के तहत भारत के हिंद–प्रशांत ढांचे का भी समर्थन किया गया। सत्र में चर्चा के दौर. ान, बंदरगाह का आधुनिकीकरण– आर्थिक विकास और समग्र क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में उभरा, जो अफ्रीका में उन्नत व्यापार, नि. वेश और समृद्धि से भरपूर भविष्य का वादा करता है। ओएसडी (ईआर एंड डीपीए) श्री पी. कुमारन, विदेश मंत्रालय ने इस बात को रेखांकित किया कि अफ्रीका में भारत का निवेश बढ़ रहा है, जो अफ्रीका के साथ बढ़ती आर्थिक भागीदारी और साझेदारी को दर्शाता है। यह बहुआयामी, स्थायी समर्पण का प्रतीक है जो दोनों देशों के समग्र विकास को बढ़ाने का वादा करता है। ■

समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी)

समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी) विभिन्न अनुसंधान और नी. तिगत सलाहकार पहलों में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हुए भारत के समुद्री क्षेत्र और इसके व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसका एक उल्लेखनीय योगदान 2 जून, 2023 को राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड को सौंपी गई सीएमईसी नीतिगत सलाह है। "अ कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द मैरीटाइम ट्रां. सपोर्ट अग्रीमेंट्स ऑफ बिम्सटेक नेशन्स एंड द वे फॉरवर्ड" शीर्षक से यह समग्र रिपोर्ट बिम्सटेक (बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल)राष्ट्रों में समुद्री परिवहन समझौतों पर प्रकाश डालती है।

इसके अतिरिक्त, सीएमईसी ने ''एक्सपेंडिंग कॉन्टूअर्स ऑफ इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर" रिपोर्ट का प्रकाशन किया है, जो हितधारकों के साथ व्यापक विमर्श का परिणाम है। 19 अप्रैल, 2023 को कोलकाता में आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन पर आधारित यह रिपोर्ट भारत के समुद्री क्षेत्र के उभरते परिदृश्य पर प्रकाश डालती है। यह प्रमुख रुझानों, चुनौतियों और अवसरों की रूपरेखा के साथ, भारत के समुद्री उद्योग के भविष्य को आकार देने में संलग्न नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए उपयोगी संसाधन का कार्य करती है। हितधारकों के साथ व्यापक मंत्रणा के बाद प्रस्तुत यह रिपोर्ट भारत–बांग्लादेश कनेक्टिविटी के संबंध में ऐसे अहम मुद्दों और समस्याओं को सामने रखती है, जिन पर प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इस खंड में भारत–बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी और उसके अतिरिक्त

बाधाओं को दूर करने के 'कार्रवाई बिंदु' शामिल हैं।

इसके अलावा, सीएमईसी ने "भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री सहयोग के संभावित क्षेत्रों" के बारे में इनपुट प्रदान करके पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएस एंड डब्ल्यू) के साथ सक्रिय सहयोग किया है। साथ ही सीएमईसी ने हिंद–प्रशांत महासागर पहल स्तंभ 7: व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन के संबंध में बेहद उपयोगी जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे विदेश मंत्रालय (एमईए) को सौंप दिया गया।

इसके अलावा, सीएमईसी ने दो नीतिगत सारांश जारी किए हैं, जो समुद्री कनेक्टिवि. टी और क्षेत्रीय विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का संक्षिप्त, लेकिन प्रभावशाली विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।'"राइडिंग द वेव्ज: सम आइडियाज ऑन कनेक्टिविटी इन बे ऑफ बंगाल" बंगाल की खाड़ी में कनेक्टि. विटी के महत्व का आकलन करता है और इसे बढ़ाने के लिए नवीन विचार प्रस्तुत करता है। इस बीच, "ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सिटवे पोर्ट एंड व्हॉट इट मीन्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी इन बे ऑफ बंगाल" जो संभावित लाभ और भविष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए सिटवे पोर्ट के संच. ालन के महत्व और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इसके निहितार्थ का अन्वेषण करता है।

सीएमईसी अपने न्यूज़लेटर, "मैरीटाइम ब्रीफिंग" का प्रकाशन निरंतर जारी रखे हुए है। अब तक इसके कुल 8 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सीएमईसी–ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, स्ट्रेंगथनिंग बाइलैटरल टाइज : "यूएसए एंड इंडिया कलैबरैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैरीटाइम सेक्टर", चटगांव– मोंगला पोर्ट एग्रीमेंट, और इंडियाज फोकस ऑन चाह. बहार, एन्हेंसिंग इट्स मैरीटाइम कनेक्टिविटी एफर्ट्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी समीक्षाएं प्रस्तुत कर रहा है।

सीएमईसी ने एक बेहद व्यापक और विल. क्षण आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के बीच एक निर्बाध ज्ञान साझा. करण नेटवर्क बनाना है। यह सूचना को सुव्यवस्थित तरीके से प्रदान करना और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के बारे में उसे फीडबैक देना सुनिश्चित करेगा। इस संदर्भ में, सीएमईसी ने व्यापक हितधारकों तक पहुंच कायम की है, जिनमें डेनमार्क, ब्रिटेन, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, इंडा. नेशिया आदि जैसे प्रमुख समुद्री देश शामिल हैं। आउटरीच कार्यक्रम में प्रमुख उद्योग, व्यापार संघ, थिंक टैंक, शैक्षणिक संस्थान आदि शामिल हैं। गहन तुलनात्मक अध्ययन से लेकर व्यावहारिक नीतिगत सारांश, समीक्षाओं और समुद्री उद्योग के महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ बैठक तक सीएमईसी, भारत के समुद्री क्षेत्र की उन्नति में योगदान देने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा है। ■

टी–20 शिखर सम्मेलन
टी–7 और टी–20 का संयुक्त अधिवेशन

टी–20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त अधिवेशन के दौरान प्रतिभागी

मैसूरु में थिंक–20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर 30 जुलाई, 2023 को आ. रआईएस और एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट (एडीबीआई) ने टी–7 और टी–20 नेतृत्व तथा अन्य शिक्षाविदों और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञों के साथ एक साझा बैठक की। यह बैठक –बहु संकट के समाधान और 2030 एजेंडा को फिर से ताजा करने पर कार्रवाई करने संबंधी जी–7/जी–20 के संयुक्त आह्वान पर विचार–विमर्श करने के लिए आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक और टी–20 इंडिया कोर कमेटी के सदस्य प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के आरंभिक भाषण से हुई। आईडीएसए के महानिदेशक और टी–20 इंडिया के अध्यक्ष राजदूत सुजान चिनॉय, टी–7 जापान के लीड चैयर और एडीबीआई के सीईओ प्रोफेसर टी. सोनोबे, ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव के अध्यक्ष प्रोफेसर डेनिस स्नोवर ने टी–7 और टी–20 के बीच सहयोग बढ़ाने पर संक्षिप्त भाषण दिए।

इसके पश्चात खुली चर्चा हुई जिसमें अन्य प्रतिभागियों ने विशेष रूप से एसडीजी, जलवायु वित्त और ग्लोबल साउथ की चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर अपने सुझाव और सिफारिशें प्रदान कीं। प्रोफेसर बंबांग ब्रोडजोनगोरो, इंडोनेशिया के पूर्व अनुसंधान और प्रौद्योगिकी/राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार एजेंसी मंत्री, श्री निकोला बाउचोड, डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम, सदस्य – एचआर, क्षमता निर्माण आयोग, भारत सरकार, डॉ. लुकोवी सेके, अफ्रीकी संघ विकास एजेंसी–एनईपीएडी, दक्षिण अफ्रीका, डॉ. ताबिया लिसनर, अनुसंधान निदेशक, जीएसआई, राजदूत कारामुरु डी पाइवा, सलाहकार, सीईबीआरआई, डॉ. होजे पियो बोर्गेस, अध्यक्ष, सीईबीआरआई, डॉ. जूलिया डायस लेइट, सीईओ, सीईबी. आरआई, सुश्री लुसियाना गामा मुनिज़, डॉ. एलिजाबेथ सिदिरोपोलोस, साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, दक्षिण अफ्रीका की मुख्य कार्यकारी, डॉ. एंटोनियो विलाफ्रांका, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज एंड को–हैड, यूरोप एंड ग्लोबल गवर्नेंस सेंटर, प्रोफेसर डॉ. अन्ना–कैथरीना हॉर्निज, निदेशक, जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी (आईडीओएस), डॉ. निकोलस जे.ए. बुचौड, ग्रैंड पेरिस एलायंस फॉर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट, फ्रांस के सह–संस्थापक और अध्यक्ष, डॉ. फैबियो सोरेस, शोधकर्ता, इंस्टीट्यूटो डी पेस्क्विसा इकोनोमिका अप्लिकाडा, ब्राजील, डॉ. प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस, डॉ. सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस, और डॉ. बीना पांडे, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस ने बैठक में भाग लिया। ■

डीकार्बोनाइजेशन और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं: आसियान और भारत के लिए सहयोग की गुंजाइश

पृथ्वी अपने अस्तित्व से संबंधित खतरे की कगार पर है। पहली औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधन पर आधारित अनियंत्रित आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गिरावट और वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) का निर्माण हुआ, जिससे वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि हुई। वैज्ञानिक साक्ष्य यह संकेत दे रहे हैं कि यदि जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए वैश्विक स्तर पर तत्काल मौलिक उपाय नहीं किए गए, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, भारत और आसियान दोनों जलवायु परिवर्तन के संभावित नकारात्मक प्रभावों जैसे समुद्र के बढ़ते स्तर, मौसम की चरम स्थितियों, वर्षा के बदलते पैटर्न के प्रति बेहद असुरक्षित हैं। इसलिए, जलवायु परिवर्तन से निपटना और स्थायी हरित ऊर्जा स्रोतों का रुख करना दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। पेरिस समझौते के तहत, भारत और आसियान के सदस्य देशों, दोनों ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है। यद्यपि, डीकार्बोनाइजेशन मुश्किल है और इसके आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं।

भारत और आसियान में डीकार्बोना. इजेशन के आर्थिक निहितार्थों और सहयोग के संभावित दायरे को समझने के लिए आरआईएस में आसियान–भ. ारत केंद्र ने 18 अक्टूबर 2023 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में डॉ. बद्री नारायणन जी, प्रवासी फेलो, नीति आयोग और संबद्ध संकाय सदस्य, स्कूल् ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री साइंस,यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सिएटल मुख्य वक्ता थे। डॉ. नारायण ान ने 2010 और 2020 के बीच सभी आसियान क्षेत्रों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित करते हुए अपनी प्रस्तुति शुरू की। उन्होंने दलील दी कि आसियान देशों को 2030 तक उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य पूरा करने के लिए बिना शर्त संकल्प के तहत उत्सर्जन में 11 प्रतिशत और सशर्त संकल्प के तहत 24 प्रतिशत कमी लाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने इंगित किया कि कार्बन कटौती का लक्ष्य भले ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इससे भारत और आसियान दोनों में जीडीपी के साथ–साथ व्यापार वृद्धि पथ पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत और आसियान को कम से कम नुकसान और उत्सर्जन में अधिक प्रभावी कमी के लिए उत्सर्जन व्यापार पर विचार करना चाहिए। डॉ. नारायण ान की प्रस्तुति के बाद इस बारे में गहन चर्चा हुई। ■

"चंद्रयान–3 के बाद विश्वविद्यालय–उद्योग–स्टार्टअप नवाचार संबंधों को सुदृढ़ बनाना"

माईगोव और आरआईएस के बीच सहयोग के तहत 27 अक्टूबर 2023 को "चंद्रयान–3 के बाद विश्वविद्यालय–उद्योग–स्टार्टअप नवाचार संबंधों को सुदृढ़ बनाना" विषय पर वर्चुअल सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को साथ जोड़ना और उन्हें सुदृढ़ विश्वविद्यालय–उद्योग–स्टार्टअप नवाचार संबंधों की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना था। इसके प्रतिभागियों में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/और अन्य स्वायत्त निकायों के विद्यार्थी शामिल थे। यह सत्र चंद्रयान–3 की सफलता का गुणगान करने का साधन रहा तथा इसने आरआईएस और "यूनिवर्सिटी कनेक्ट" संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत बनाते हुए माईगोव के चंद्रयान महा क्विज़ को सफलतापूर्वक प्रच. ारित किया। सत्र की शुरुआत आरआईएस में साइंस डिप्लोमेसी फेलो, राजदूत भास्कर बालाकृष्णन के प्रारंभिक भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने पिछले वर्ष के इसरो मिशनों की सफलताओं और आदित्य एल1 और गगनयान सहित आगामी मिशनों पर प्रकाश डालते हुए सत्र के उद्देश्य के बारे में संक्षेप में बताया।

इसरो मुख्यालय में क्षमता निर्माण और सार्वजनिक आउटरीच के निदेशक श्री सुधीर कुमार एन ने मुख्य वक्ता के तौर पर अपने संबोधन में विश्वविद्यालयों, उद्योगों और स्टार्टअप के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने किसी भी कार्य की सफलता में संस्थागत संस्कृति और टीम वर्क की भूमिका को रेखांकित करते हुए चंद्रयान–3 की सफलता का मंत्र साझा किया।

माईगोव की ओर से श्री उपेन्द्र उपाध्याय एवं श्रीमती गरिमा तिवारी ने चंद्रयान–3 युग के बाद विश्वविद्यालय–उद्योग–स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने में डेटा एनालिटिक्स और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने क्विज का औचित्य बताया और उसके बारे में जानकारी देते हुए उपस्थित लोगों को उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

आरआईएस के डॉ. चैतन्य गिरि ने पूरे सत्र का संचालन करते हुए चर्चाओं का सार समझाया तथा नवाचार और सहयोग की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

सुकृत जोशी, आरआईएस ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करके सत्र का समापन किया। अंततः कहा जा सकता है कि इस सत्र ने चंद्रयान–3 के पश्चात के दौर में सुदृढ़ विश्वविद्यालय–उद्योग–स्टार्टअप संबंधों को बढ़ावा देने की आधारशिला रखी। ■

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स उद्योग : भारत और जी–20 के परिप्रेक्ष्यों से नीतिगत और नियामक परिदृश्य विकसित करना

दुनिया भर के वित्तीय क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाया जा रहा है, जिसकी परिणति वर्चुअल डिजि. टल एसेट्स (वीडीए) उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि में हुई है। भारत और अन्य उभरते बाजारों में (मुद्राओं, क्रिप्टो परिसंपत्तियों, अपूरणीय या नॉन–फंजिबल टोकन, विकेन्द्रीकृत वित्त आदि सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स उद्योग का आकार बढ़ रहा है। भारत की जी–20 की अध्यक्षता के फाइनेंस ट्रैक ने एक नियामक ढांचा लाने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विकास का संज्ञान लिया है। उभरते बाजारों में इस क्षेत्र महत्व देखते हुए आरआईएस ने भारत वेब3 एसोसिएशन (बीडब्ल्यूए) के सहयोग से 11 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में "वर्चुअल डिजिटल एसेट्स उद्योग : भारत और जी–20 के परिप्रेक्ष्यों से नी. तिगत और नियामक परिदृश्य विकसित करना" विषय पर एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। इस गोलमेज चर्चा में उद्घाटन सत्र के अलावा दो तकनीकी सत्र भी थे। तकनीकी सत्रों में भारत में वीडीए उद्योग के रुझानों, अवसरों और चुनौतियों और जी–20 में विकास के उपयुक्त संदर्भ के साथ विकसित होते नीतिगत और शासन परिदृश्य को शामिल किया गया।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और श्री दिलीप चेनॉय, अध्यक्ष, भारत वेब3 एसोसिएशन ने अपने प्रारंभिक भाषणों में उभरते बाजारों में वित्त क्षेत्र के इस उभर रहे इस खंड की व्यापक रूपरेखा को रेखांकित किया। तकनीकी सत्र–1 की अध्यक्षता करते हुए श्री संतोष जॉर्ज, मुख्य कार्यकारी अधिक. ारी, आरईबीआईटी, मुंबई ने एक केंद्रीय बैंकर के रूप में इस विषय पर अपना परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। इस सत्र में वीडीए उद्योग के विभिन्न तकनीकी प्लेटफार्मों जैसे एआई, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ वैल्यू, वेब3 आदि द्वारा प्रस्तुत व्यापार और निवेश के अवसरों, उभरते रुझानों तथा नीतिगत और नियामक सरोकारों के बारे में चर्चा की गई। सत्र में महाराष्ट्र सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों के उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में विकेंद्रीकृत वित्त के बढ़ते उपयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

तकनीकी सत्र–2 की अध्यक्षता श्री दिलीप चेनॉय ने की। इस सत्र में क्रिप्टो मुद्राओं के संबंध में विकासशील देशों के समक्ष नीतिगत चुनौतियों, भारत और जी–20 द्वारा उठाए गए कदमों और विभिन्न नियामक क्षेत्रों पर उद्योग की प्रतिक्रिया और अपेक्षाओं पर चर्चा की गई। वीडीए उद्योग द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक मानकीकृत नियामक ढांचे की आवश्यकता है। डॉ प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने गोलमेज़ चर्चा के मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए। ■

आयुर्वेद: विश्व के लिए कल्याण का समग्र विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला में 15–16 अगस्त 2023 को 'आयुर्वेदः विश्व के लिए कल्याण का समग्र विज्ञान' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह जी–20/टी–20 पक्ष समर्थन कार्यक्रम आरआईएस, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) द्वारा संयुक्त रूप से आयो. जित किया गया। स्वास्थ्य देखभाल के लिए वैश्विक स्तर पर समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया।

आयुष मंत्रालय के सचिव डॉ. राजेश कोटेचा ने इसमें उद्घाटन भाषण दिय. ा। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में निरीक्षण, उपचार, निगरानी और शमन के लिए एक एकीकृत, अंतःविषयक दृष्टिकोण का आह्वान करने वाली 'वन हेल्थ' की अवधारणा की ओर ध्यान आकृष्ट किया। सम्मानित अतिथि के रूप में आरआईएस के महानिदेशक डॉ. सचिन चतुर्वेदी ने स्वास्थ्य के लिए अंतःविषयक दृष्टिकोण की उपयुक्तता और विकास के लिए मानव–केंद्रित दृष्टिकोण की उपयुक्तता पर बल दिया। उन्होंने पा. रंपरिक चिकित्सा के लिए जी–20 फोरम की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। उद्घाटन सत्र के बाद नौ सत्रों में 17 वक्ताओं ने प्रस्तुति दी, जिनमें 'आयुर्वेद और समग्र कल्याण', आयुर्वेद में जीवन शैली और आहार का एकीकरण, आयुर्वेद और मानसिक कल्याण' पर चर्चा शामिल रही। सत्रों में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गईं, उदाहरण के लिए निवारक और पूर्वानुमानित चिकित्सा पर आधारित सत्र में बताया गया कि आयुर्वेद कैसे निवारक, पूर्वानुमानित, वैयक्तिकृत और सहभागि. तापूर्ण है। पी 4 चिकित्सा आधुनिक

स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली में उभरता हुआ नया परिप्रेक्ष्य है और आयुर्वेद इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 'वृद्धों का कल्याण' विषय पर आयोजित सत्र में स्वस्थ वृद्ध ावस्था में आयुर्वेद की भूमिका पर चर्चा की गई। अन्य महत्वपूर्ण सत्र 'हर्बल और पशु जगत का कल्याणः वृक्षायुर्वेद और अश्वायुर्वेद' पर थे, जिनमें पशु स्वास्थ्य और पौधों के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद की उपयुक्तता पर जोर दिया गया। इसके वक्ताओं में डॉ मंजूनाथ प्रो–वाइस चांसलर एसवीवाईएएसए विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक, रामकुमार कुट्टी, संस्थापक निदेशक, वैद्यग्राम, कोयंबटूर, तमिलनाडु, डॉ सुहास कुमार शेट्टी प्रधाना. चार्य, केएलई आयुर्वेद कॉलेज, बेलगाम, कर्नाटक, डॉ राम जयसुंदर, वैज्ञानिक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, डॉ. बी.एस. प्रसाद, अध्यक्ष आयुर्वेद बोर्ड, एनसीआईएसएम, नई दिल्ली और डॉ सारिका चतुर्वेदी वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ डी वाई पाटिल, विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र शामिल थे। ■

टीएफ–3 और टीएफ–6 अध्यक्षों और सह–अध्यक्षों की संयुक्त बैठक

कार्यबलों की संयुक्त बैठक में प्रतिभागियों का समूह

मैसूरु में टी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान आरआईएस ने 01 अगस्त, 2023 को कार्यबलों के सह–अध्यक्षों–टास्क फोर्स 3–'लाइफ, अनुकूलन और कल्याण के लिए नैतिक मूल्य' और टास्क फोर्स 6– 'एसडीजी में तेजी लाना : 2030 के एजेंडे के लिए नए रास्ते तलाशना' की एक संयुक्त बैठक आयोजित की। इन कार्यबलों के सह–अध्यक्षों ने भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों और तौर–तरीकों पर चर्चा की। एसडीजी और लाइफ से संबंधित मुद्दों पर सहयोग के लिए अंतर्दृष्टिपूर्ण टिप्पणियां और सिफारिशें की गईं। इस संयुक्त बैठक में टीएफ–3 और टीएफ–6 के प्रमुख अध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, नई दिल्ली, रा. जदूत सुजान आर. चिनॉय, महानिदेशक, एमपी–आईडीएसए, नई दिल्ली, सुश्री कल्पना शास्त्री रेगुलेगेडा, प्रबंध निदेशक, एजी–हब फाउंडेशन, हैदराबाद, और जी. ए. तड़स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस, नई दिल्ली ने भाग लिया।

बैठक में दोनों कार्यबलों के सह–अध्यक्षों और अन्य आमंत्रित हस्तियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इनमें औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी), नई दिल्ली के निदेशक और मुख्य कार्यकारी डॉ. नागेश कुमार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बेंगलुरु के निदेशक डॉ. शैलेश नायक, द तक्षशिला इंस्टीट्यूशन इंडिया की अनुसंधान प्रमुख डॉ. शांभवी नाइक, साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, साउथ अफ्रीका की चीफ एक्जीक्यूटिव डॉ. एलिज़ाबेथ सिदिरोपोलोस, इंस्टीट्यूटो डी पेस्क्विसा इकोनोमिका अप्लिकाडा, ब्राज़ील, के शोधकर्ता, डॉ. फैबियो सो. रेस, सेंटर फ़ॉर पॉलिसी डायलॉग (सीप. ीडी), बांग्लादेश, में कार्यकारी निदेशक डॉ. फ़हमीदा खातून, अफ्रीकन यूनियन डेवलेपमेंट एजेंसी–एनईपीएडी, साउथ अफ्रीका के डॉ. लुकोवी सेके, अफ्रीकन यूनियन डेवलेपमेंट एजेंसी–एनईपीएडी, साउथ अफ्रीका की डॉ.पामला गोपाल, एलपीईएम एफईबी यूआई (इंस्टीट्यूट फॉर इकॉनोमिक एंड सोशल रिसर्च फेकल्टी ऑफ इकॉनोमिक्स एंड बि. जनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, की निदेशक डॉ. रियातु मारियातुल कि. ब्तय्याह, नीति आयोग, भारत सरकार, में सीनियर फेलो, डॉ. आशीष कुमार, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, नई दिल्ली, के अध्यक्ष श्री अशोक खोसला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, भारत में प्रोफेसर, डॉ. देबोलिना कुंडू, क्षमता निर्माण आयोग, भारत सरकार में सदस्य (एचआर),डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम, विक. ासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सब्यसाची साहा, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी), भारत, के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आउटरीच डिवीजन में एसोसिएट डायरेक्टर और सीनियर फेलो डॉ. शैली केडिया, एनआईपीओ, भारत के अध्यक्ष, डॉ. टी. सी. जेम्स, यूनिवर्सिटास गदजाह माडा, इंडोनेशिया में प्रोफेसर, डॉ. दनांग

Continued on page 17...

हिंद–प्रशांत आर्थिक ढांचा: मुद्दे और आगे की राह

आरआईएस ने नई दिल्ली में 7 अगस्त 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज (आईएसएएस), एनयूएस, सिंगापुर के साथ 'हिंद–प्रशांत आर्थिक ढांचा: मुद्दे और आगे की राह' विषय पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और आईएसएएस–एनयूएस के निदेशक डॉ. इकबाल सिंह सेविया के आरंभिक भाषण से हुई, जिसमें दोनों ने हिंद–प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) के महत्व, समझौता वार्ता में इसकी वर्तमान अवस्था की स्थिति और क्षेत्र के अन्य क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से इसकी भिन्नता के बारे में चर्चा की। इसके बाद दोनों संस्थानों द्वारा आईपीईएफ पर दो विस्तृत प्रस्तुतियां पेश की गईं और श्री सुमंत चौधरी, सीआईआई, सुश्री आर.वी. अनुराधा, क्लारस लॉ एसोसिएट्स और सुश्री नीला मोहनन, संयुक्त सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा विवेचना/टिप्पणियां की गईं।

आईएसएएस के डॉ. अमितेंदु पालित की विस्तृत प्रस्तुति के साथ चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ा। उन्होंने आईपीईएफ की प्रमुख विशेषताओं–दुनिया की 1/3 आबादी के साथ सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक होने, विश्व अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रभुत्व के व्यापक स्तर सहित सदस्य देशों के बीच आर्थिक विविधताएं होने–के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नए समझौते के आरसीईपी और एपीईसी सहित कई क्षेत्रों के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। आरआईएस की ओर से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और प्रोफेसर एस.के. मोहंती की प्रस्तुति में क्षेत्र और भारत के दृष्टिकोण से चार आईपीईएफ स्तंभों की प्रासंगिकता के साथ ही साथ इन स्तंभों से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बात को रेखांकित किया गया कि भारत क्षेत्रीय सदस्यों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और इन अर्थव्यवस्थाओं को विशाल बाजार पहुंच प्रदान कर सकता है। हालांकि, भारतीय घरेलू नीति और आईपीईएफ समझौते के बीच अंतर है, जिसको भारत के हितों के उपयुक्त बनाने के लिए दूर किए जाने की आवश्यकता है।

चर्चा में भाग लेने वालों–श्री चौधरी, सुश्री अनुराधा और सुश्री मोहनन ने सदस्यों के बीच भू–राजनीति, स्वच्छ ऊर्जा स्तंभ और आईपीईएफ के निष्पक्ष अर्थव्यवस्था स्तंभ से संबंधित कई मुद्दों को रेखांकित किया। चर्चा को श्री प्रणव कुमार, राजदूत गोयल, श्री राजीव खेर, डॉ. चारी, प्रोफेसर प्रबीर डे जैसे विशेषज्ञों और आरआईएस के अन्य संकाय सदस्यों ने भी अपने विचारों से समृद्ध किया। बैठक का समापन आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के संबोधन के साथ हुआ, जिन्होंने कोविड–19 के बाद आपूर्ति बाधाओं की मौजूदगी में आईपीईएफ का लाभ उठाने के महत्व को रेखांकित करते हुए चर्चा समाप्त की। ■

सहभागिता की कमियां दूर करना और एसएजीई के दायरे का विस्तार करना

आरआईएस में दक्षिण एशियाई ऊर्जा समूह (एसएजीई) ने अपनी भविष्य की कार्य योजना के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए 20 जुलाई 2023 को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। श्री आर वी शाही की अध्यक्षता में संपन्न यह बैठक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाई। विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ एसएजीई की सहभागिता की कमियों को दूर करने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए श्री आरवी शाही ने सहभागिता के प्रत्येक चरण में विदेश मंत्रालय से इनपुट मांगने के महत्व पर जोर दिया। राजदूत प्रीति सरन ने भविष्य में एसएजीई बैठकों के लिए भारत में उच्चायुक्तों और स्थानीय राजदूतों तक पहुंच कायम करने का सुझाव दिया। उन्होंने निजी संबंधों से लाभ उठाने तथा विदेश सचिव और विदेश मंत्री सहित विदेश मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों को शामिल करने की सिफारिश की। इसके अलावा, उन्होंने भविष्य की एसएजीई बैठकों में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा।

बैठक में सामूहिक रूप से निर्णयों को प्राथमिकता देने के महत्व पर चर्चा की गई और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रमुख हितधारकों की पहचान की गई। राजदूत प्रीति सरन ने देश से संबंधित एसएजीई की रिपोर्टों के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), यूएसएआईडी और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसे संगठनों के साथ सामंजस्यपूर्ण समन्वय बैठकों का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सार्वजनिक संगोष्ठियों और हितधारक चर्चाओं के माध्यम से एसएजीई के काम को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की। श्री अनिल सरदाना ने आवश्यक होने की स्थिति में यूएसएआईडी द्वारा वित्त पोषित बाहरी सलाहकारों को शामिल करने के विकल्प सहित, प्रत्येक देश के लिए रिपोर्ट को कार्यान्वयन योग्य योजनाओं में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा। भविष्य की परियोजनाओं की व्यावसायिक व्यवहार्यता के आकलन और संबंधित देशों में परियोजनाओं के लिए निविदा दस्तावेजों के निर्माण पर भी चर्चा की गई।

बैठक में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे अन्य ऊर्जा क्षेत्रों को शामिल करके एसएजीई के दायरे को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्री अजय शंकर ने प्रभावी मांग–पक्ष नीति के रूप में घरों के लिए रसोई गैस के महत्व पर बल देते हुए सुझाव दिया कि यह एसएजीई के अधिदेश के विस्तार के आधार के रूप में काम कर सकता है। श्री राकेश नाथ ने भविष्य की बैठकों के लिए ओएनजीसी से प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। ■

जी–20 नेताओं का नई दिल्ली घोषणा पत्र: अनुकूलन हेतु लाइफ और बुनियादी ढांचे के लिए आगे की राह

जी–20 नेताओं के नई दिल्ली घोषणा पत्र पर 'अनुकूलन हेतु लाइफ और बुनियादी ढांचे के लिए आगे की राह' शीर्षक से 15 सितंबर, 2023 को वेबिनार आयोजित किया गया। सत्र का आरंभ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के प्रारंभिक भाषण से हुआ, जिसमें जी–20 नेताओं के घोषणा पत्र द्वारा लाइफ, एसडीजी और अवसंरचना अनुकूलन पर गहन रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने को रेखांकित किया गया और इन कदमों को आगामी जी–20 अध्यक्षताओं के दौरान आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई है। ओईसीडी के विकास सहयोग निदेशालय में नीतिगत सुधार से संबंधित वरिष्ठ सलाहकार डॉ. रोफ्ल श्वार्ज़ ने जी–20 नेताओं के घोषणा पत्र में विकास से जुड़े पहलुओं, विशेष रूप से विकास के लिए वित्त पोषण को लाइफ, अर्थव्यवस्था और एसडीजी के अनुरूप बनाने पर जोर दिए जाने को रेखांकित किया।

येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस पोगे ने जी–20 नेताओं के घोषणा पत्र में आने वाले वर्षों में विशिष्ट दक्षिणी परिप्रेक्ष्य और मानवता के लिए दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए भारत की सराहना की। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे दस्तावेज़ पर 20 सरकारों से सहमति प्राप्त करने की उपलब्धि असाधारण है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात के लिए आगाह भी किया कि जिन लोगों को यह मुक्ति दिलाना चाहता है, उन्हें लाभ पहुंचाने में इसकी सफलता के लिए इसका प्रतिपादन महत्वपूर्ण है।

श्री निकोलस बुचौड ने अवसंरचना संबंधी वित्त पोषण और मौजूदा अवसंरचनात्मक घाटे के संबंध में ग्लोबल साउथ पर दिए गए बल को रेखांकित किया। फोर्थ सेक्टर ग्रुप के सीईओ श्री हीराद सबेती ने इस बात पर जोर दिया कि जी–20 की थीम "एक पृथ्वी, एक कुटुम्ब और एक भविष्य" केवल नारा भर नहीं है, बल्कि हमारी परस्पर संबद्ध दुनिया में रणनीतिक अनिवार्यता है। उन्होंने चर्चा में अफ्रीकी संघ सहित अधिक विचारों को शामिल करने के भारत के प्रयासों की सराहना की।

अवीवा इन्वेस्टर्स में क्लाइमेट फाइनेंस के प्रमुख श्री थॉमस टायलर ने जी–20 घोषणा पत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न उत्तरदायित्वों

Continued on page 14...

आसियान शिखर सम्मेलन प्रक्रिया और सम्बद्ध बैठकें: मुद्दे और आगे की राह

विश्व महत्वपूर्ण भू–रणनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। महा शक्तियों में प्रतिद्वंद्विता के दौर की वापसी और नयी भू–रणनीतिक अवधारणा के रूप में हिंद–प्रशांत के उद्भव ने वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये घटनाक्रम वैश्विक सुरक्षा के साथ–साथ आर्थिक संरचना को भी नया आकार दे रहे हैं। आसियान के हिंद–प्रशांत के केंद्र में होने के मद्देनजर उभरते भू–रणनीतिक और भू–आर्थिक परिदृश्य का आसियान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस बात को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं कि आसियान अपनी केंद्रीयता को कैसे बरकरार रखेगा, दक्षिण–पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग की संधि (टीएसी) की प्रासंगिकता को कैसे बनाए रख सकेगा और वर्तमान में जारी भू–रणनीतिक परिवर्तन से उपजी आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से कैसे निपटेगा।

भारत सहित आसियान के सदस्य देश और उसके संवाद भागीदार इन उभरते मुद्दों पर विचार करने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में जकार्ता में एकत्र हुए। भारत की आसियान के सदस्य देशों के साथ विशेष रूप से गैर–पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों, उद्योग 4.0 और डिजिटल रूपांतरण और अन्य समसामयिक मुद्दों के संबंध में साझा चिंताएं हैं।

तेजी से बदलती इस दुनिया में आसियान और भारत के सामने आने वाले मुद्दों और 20वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन से अपेक्षाओं को समझने के लिए आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने 4 सितंबर 2023 को एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। मौजूदा भू–रणनीतिक/भू–आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आसियान–भारत संबंधों पर मंथन से संबंधित चर्चा में भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के विशेषज्ञों ने भाग लिया और आगे की राह के बारे में सुझाव दिए। प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से इस बात पर जोर दिया कि साझा मूल्यों और सामान्य भू–राजनीतिक चिंताओं के मद्देनजर आसियान–भारत साझेदारी त्वरित गति से बढ़ी है। यद्यपि उनकी दलील थी कि आसियान–भारत संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में आसियान–भारत सहयोग का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। प्रतिभागियों ने इस बात का भी समर्थन किया कि आसियान और भारत को व्यापारिक संबंधों को और अधिक संतुलित बनाने के लिए सेवा व्यापार में तेजी लाने, कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ■

डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्त, समावेशन और जी–20 घोषणा पत्र पर पैनल चर्चा

डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ ही दुनिया ने दूसरे मशीनी युग में प्रवेश कर लिया है। डिजिटलीकरण ने हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में पैंठ बना ली है। भौतिक गतिविधियों के विपरीत, डिजिटल प्रौद्योगिकी वास्तविक समय में सीमाओं को पार कर जाती है।

ऐसे में यह आवश्यक है कि देश सवंर्धित डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ें और डिजिटलीकरण के फायदों से लाभान्वित होने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दें। भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजि. टल भुगतान शुरू करके सफलता की राह दिखायी है। डिजिटलीकरण कुशल और पारदर्शी शासन का भी एक महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है।

राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल हेल्थकेयर इकोसिस्टम, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की दिशा में बेहद मददगार रहेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इस दिशा में उठाया गया एक अनुकरणीय कदम है। दरअसल, कोविड–19 वैक्सीन की डिजिटल डिलीवरी के लिए भारत के कोविन पोर्टल ने दर्शाया है कि स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे का डिजिटलीकरण पहुंच और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। भारत की गवर्नमेंट ई–मार्केट (जीईएम) नीति पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए व्यापार में सुगमता बढ़ाती है। क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रही है, जिसके प्रभावी विनियमन के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का भारत का प्रस्ताव इस दिशा में समुचित कदम है, जो प्रत्येक देश के लिए वास्तविक समय में सूचना तक पहुंच को सक्षम बनाएगा।

चाहे कितने ही ऊंचे लक्ष्य या मानक निर्धारित किए गए हों, उन्हें प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता अपरिहार्य है। हम एक पृथ्वी को साझा करते हैं और सभी के कल्याण की आकांक्षा रखते हैं, ऐसे में यह आवश्यक है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भौतिक साधन उपलब्ध कराने में देश सहयोग करें। विकासशील देशों को आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के जरिए गरीबी उन्मूलन के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, सतत विकास ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। यद्यपि इसे हासिल करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं को क्रमिक वित्त पोषण प्रदान करने की आवश्यकता है। बढ़े हुए वित्त पोषण से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलने के साथ–साथ यह उन्हें इसके अनुकूल ढलने में भी सक्षम बनाएगा। इसके अलावा, यह हरित भविष्य की दिशा में उन्मुख निष्पक्ष और समावेशी परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विभिन्न अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को पुनर्गठित करने और उनका रुख बदलने की आवश्यकता है। क्रेडिट रेटिंग के प्रति आकर्षण सतत विकास नीतियों के लिए धन तक पहुंच कायम करने में एलएमआईसी के लिए रुकावट का कार्य करता है। विकासशील देशों में ढांचागत परियोजनाओं के कार्बन उत्सर्जन की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिसके लिए परियोजना के आधार पर धन की आवश्यकता है, न कि क्रेडिट रेटिंग के

Continued on page 17...

Continued from page 13...

और समान हितों को शामिल करने का विचार भी रखा।

एसआईएएन, वित्त मंत्रालय, ब्राजील में सतत विकास वित्त के उप सचिव डॉ. इवान ओलिवेरा ने भारत की जी–20 अध्यक्षता के दौरान विशेषकर विकास संबंधी वित्त पोषण, एसडीजी और वित्त पोषण को एसडीजी के अनुरूप बनाने के संदर्भ में उत्पन्न गति को आगे बढ़ाने के महत्व पर बल दिया।

दक्षिण अफ्रीका के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डायलॉग के शोधकर्ता श्री मिकाटेि कसो कुबायी ने एक नए विकास परिप्रेक्ष्य के रूप में लाइफ पर बल दिया, जिसमें बहुपक्षीय संगठनों में सतत विकास, वित्त पोषण और सुधार के सभी तत्व शामिल हैं। आरआईएस में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सब्यसाची साहा ने पॉट्सडैम क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में रेखांकित ग्रहीय सीमा के अतिक्रमण की की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जी–20 घोषणापत्र में लाइफ को एक नए परिप्रेक्ष्य के रूप में शामिल किए जाने और सतत विकास की जीवन शैली पर उच्च–स्तरीय सिद्धांतों पर आम सहमति की सराहना की। उन्होंने लाइफ की अवधारणा को मूर्त रूप देने में टी–20 टास्क फोर्स 3 के योगदान के बारे में भी विस्तार से बताया।

जीआईजीए, जर्मनी की अध्यक्ष प्रोफेसर अमृता नार्लीकर ने "एक पृथ्वी, एक कुटुम्ब और एक भविष्य" विषय के दार्शनिक आधार पर जोर दिया, ''जिसमें केवल मानव परिवार ही नहीं, बल्कि समस्त जीवित प्राणियों को हमारे सामूहिक परिवार के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत की जी–20 की अध्यक्षता के केंद्रीय विषय के रूप में पार–प्रजातियों या ट्रांस स्पीशिज संतुलन पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है। इन संक्षिप्त टिप्पणियों के बाद, एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र शुरू हुआ, जिसमें वक्ता और प्रतिभागी दिलचस्प और विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल हुए। अंत में, डॉ. सब्यसाची साहा ने वक्ताओं और प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन दिया। ■

लाइफ अर्थव्यवस्था रणनीति

आरआईएस ने आगामी लाइफ अर्थव्यवस्था रणनीति के संबंध में फोर्थ सेक्टर ग्रुप के साथ 9 सितंबर 2023 को हाइब्रिड गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। इस गोलमेज चर्चा में आगामी 'लाइफ अर्थव्यवस्था पर जी–20 वैश्विक शिखर सम्मेलन–सिद्धांतों से लेकर अभ्यास तक' तथा व्यापक लाइफ अर्थव्यवस्था अनुसंध. ान और नवाचार एजेंडे के साझेदार और सहयोगी शामिल हुए।

बैठक की शुरुआत आरआईएस के मह. ानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के आरंभिक भाषण से हुई। उन्होंने मिशन लाइफ को शामिल करते हुए नए विक. ास परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पर चर्चा की और लाइफ अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

लाइफ अर्थव्यवस्था के बारे में सम्मेलन आयोजित करने के प्रति लक्षित यह चर्चा विभिन्न हितधारकों अर्थात् सिविल सोसायटी संगठनों, सरकारों, निजी प्र. तिनिधियों की भागीदारी से संपन्न हुई। आगामी शिखर सम्मेलन का लक्ष्य लाइफ के लिए एक वैचारिक रूपरेखा तैयार करना तथा लाइफ अर्थव्यवस्था के लिए समाधान और विचार प्रदान करने हेतु एक अनुसंधान संघ को संस्थागत बनाना था।

प्रमुख निष्कर्ष:

- लाइफ अर्थव्यवस्था का समग्र दृष्टिकोण: वैचारिक रूपरेखा से आगे बढ़ने के लिए समग्र प्रभाव के अध्ययन के महत्व पर बल देने की आवश्यकता है। लाइफ अर्थव्यवस्था को संस्थाओं के बीच पा. रदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए और लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण में सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों समाहित होने चाहिए और मिश्रित वित्त का रुख करना चाहिए, ताकि एमएसएमई की भूमिका की ओर ध्यान आकृष्ट करने सहित विशेष कर ग्लोबल साउथ में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
- एसडीजी के साथ अनुरूपता : चर्चाओं में केंद्रीय बैंकों और एमडीबी सहित वित्तीय प्रणाली को लाइफ अर्थव्यवस्था के सिद्ध ांतों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। पर्यावरण और आर्थिक प्रणालियों के बीच सर्वसम्मति स्थापित करना एक केंद्रीय विषय था, जिसने गांधी के "बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं, बल्कि जनता द्वारा उत्पादन" के विचार को प्रतिबिंबित किया गया।
- समावेशी रोजगार और जीवन शैली का दर्शन: लाइफ अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजन और लाभ के न्यायसंगत वितरण हेतु समाधानों में सक्रिय योगदान देना चाहिए। इसमें भारत के नियंत्रित उपभोग के दर्शन को शामिल किया जाना चाहिए और आजीविका के टिकाऊ साधनों की वकालत करनी चाहिए। निजी निवेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनकी मानसिकता लाइफ अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए।
- वन हेल्थ : "वन हेल्थ" अवधारणा की वकालत करते हुए मानसिक और शारीरिक कल्याण को शामिल कर स्वास्थ्य के लिए एकीकृत, समग्र दृष्टिकोण पर भी बल दिया गया। इसने लाइफ की अवधारणा को एक सार्वजनिक एजेंडा बनाने, लाइफ प्रथाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पेशकश करने तथा छोटे समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों का समर्थन करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के हरित संक्रमण, विशेषकर वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर एमएसएमई को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाना महत्वपूर्ण है। फिर भी वित्तीय वर्गीकरण के बिना उद्यम को वर्गीकृत करने का आशय यह है कि स्थानीय हरित उद्यमों (एलजीई) के लिए स्थायी वित्त का प्रवाह अनुपातहीन रूप से कम है, जो स्टार्टअप और हरित उद्यम परिवर्तन को बाधित करता है।
- एमएसएमई वित्त पोषण तक अल्प पहुंच के कारण, छोटे और सूक्ष्म उद्यम, विशेष रूप से हरित प्रथाओं को अपनाने वाले एमएसएमई अनौपचारिकता अपनाने के लिए प्रवृत्त हैं। परिवर्तन की इस विशाल क्षमता को उजागर करने के लिए, छोटे हरित उद्यमों को समर्थन देने के लिए नई सोच की आवश्यकता है।
- बांग्लादेश बैंक ने 2017 में 8 क्षेत्रों के 52 उत्पादों को सूचीबद्ध करते हुए एक हरित वर्गीकरण प्रकाशित किया। स्थायी वित्तीय प्रवाह में सहायता करने के लिए विकासशील नीतियों के संदर्भ में भारत उसका अनुसरण कर रहा है। भारतीय रि. जर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसबीआई) द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) का अधिदेश और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संबंधित हरित वित्त पोषण पहल सभी इस सकारात्मक बदलाव के उदाहरण हैं।
- मानसिकता में बदलाव लाना और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सबसे कठिन चुनौतियों में से एक भू–राजनीतिक व्यवस्था है, जिस पर बेहद पुरानी और दृढ़ मानसिकता हावी है, जिसका हमारी अर्थव्यवस्थाओं के संचालन के तरीके पर स्पिलओवर प्रभाव पड़ता है।

व्यावहारिक कदम उठाते हुए नए पि. रप्रेक्ष्य को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिनमें बातचीत की प्रकृति और गतिशीलता में बदलाव लाना; कम प्रतिनिधित्व वाले विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना; वर्तमान में जारी पि. रवर्तनों के लिए स्थानीय इकोसिस्टम की स्थापना करना; सामाजिक उद्यमियों और नवोन्मेषियों को आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन जैसी परिवर्तन पहलों में समावि. हत करना; विभिन्न समुदायों को जोड़ने वाली ट्रांस–लोकल पहल का निर्माण करना शामिल है। ये कार्रवाइयां सार्थक परिवर्तन लाने और स्थापित परिप्रेक्ष्यों को चुनौती दिए जाने को सामूहिक रूप से लक्षित कर सकती हैं। ■

जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट व्याख्यान संगोष्ठी श्रृंखला

dk;Øe dh frfFk	fo'ofo|ky; dk uke	oDrk
t|ykÃ 2023		
8 जुलाई 2023	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	राजदूत प्रीति सरन
14 जुलाई 2023	उस्मानिया विश्वविद्यालय	राजदूत गीतेश सरमा
5 जुलाई 2023	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	राजदूत प्रीति सरन
17 जुलाई 2023	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	राजदूत संजय भट्टाचार्य
17 जुलाई 2023	असम केंद्रीय विश्वविद्यालय	राजदूत लालदुथलाना राल्ते
21 जुलाई 2023	एक्सआईएम विश्वविद्यालय	राजदूत देबराज प्रधान
28 जुलाई 2023	विक्रम विश्वविद्यालय	राजदूत जे एस मुकुल
28 जुलाई 2023	बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय	श्री मनीष चांद
31 जुलाई 2023	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	राजदूत मुक्तेश परदेशी
vxLr 2023		
1 अगस्त 2023	बिट्स पिलानी (गोवा कैम्पस)	डॉ शेषाद्री चारी
3 अगस्त 2023	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रो.कन्हैया आहूजा
8 अगस्त 2023	आईआईएलएम विश्वविद्यालय	श्री पवन के वर्मा श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला
9 अगस्त 2023	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	राजदूत जे एस मुकुल
10 अगस्त 2023	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	राजदूत संजय भट्टाचार्य
14 अगस्त 2023	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	राजदूत एल.सावित्री
15 अगस्त 2023	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर	राजदूत जे.एस. मुकुल
16 अगस्त 2023	आईआईटी रूड़की	राजदूत संजय भट्टाचार्य
18 अगस्त 2023	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	राजदूत अनिल त्रिगुणायत
21 अगस्त 2023	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	राजदूत हर्ष वर्धन श्रृंगला
22 अगस्त 2023	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	राजदूत संजय भट्टाचार्य
22 अगस्त 2023	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रो.सचिन चतुर्वेदी
23 अगस्त 2023	पंजाबी विश्वविद्यालय	राजदूत नवदीप सिंह सूरी
23 अगस्त 2023	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	राजदूत अचल मल्होत्रा
23 अगस्त 2023	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान	प्रोफेसर मनीष
24 अगस्त 2023	चितकारा विश्वविद्यालय	प्रो.कन्हैया आहूजा
25 अगस्त 2023	बिट्स, पिलानी	राजदूत प्रीति सरन
26 अगस्त 2023	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर	राजदूत एल.सावित्री
27 अगस्त 2023	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	राजदूत एल.सावित्री
27 अगस्त 2023	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया	राजदूत जे.एस. मुकुल
28 अगस्त 2023	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू	राजदूत जे.के. त्रिपाठी
28 अगस्त 2023	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	राजदूत संजय भट्टाचार्य
28 अगस्त 2023	सिक्किम विश्वविद्यालय	राजदूत प्रीति सरन
28 अगस्त 2023	गुरुग्राम विश्वविद्यालय	राजदूत अचल मल्होत्रा
30 अगस्त 2023	ज़ेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट	राजदूत संजय भट्टाचार्य

fl rEcj 2023		
1 सितम्बर	भारतीय प्रबंधन संस्थान, संबलपुर	राजदूत जे.एल.त्रिपाठी
12 सितम्बर	कर्नाटक विश्वविद्यालय	श्री जी.ए. तड़स
13 सितम्बर	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड	राजदूत जे.एल.त्रिपाठी
14 सितम्बर	इलाहबाद विश्वविद्यालय	राजदूत प्रीति सरन
25 सितम्बर	दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स	प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
		राजदूत मुक्तेश परदेशी

Y20 कार्यक्रम

	fnukd	fo"k;	LFkku
t|ykÃ 2023			
1	5 जुलाई	कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0ः नवाचार और 21वीं सदी के कौशल	कोझिकोड
2	15 जुलाई	कार्य का भविष्यः उद्योग4.0ः नवाचार और 21वीं सदी के कौशल	नई दिल्ली
3	20 जुलाई	जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी	देहरादून
4	20 जुलाई	जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी	सिलीगुड़ी
5	25 जुलाई	कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0ः नवाचार और 21वीं सदी के कौशल	आइजोल
6	26 जुलाई	कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0ः नवाचार और 21वीं सदी के कौशल	अहमदाबाद
7	26 जुलाई	कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0ः नवाचार और 21वीं सदी के कौशल	इंदौर

Continued from page 14...

आधार पर, जो हर हालत में विकसित देशों के प्रति पक्षपातपूर्ण है। इसके अलावा, क्षेत्रीय भागीदारी ने यह दर्शाया है कि दक्षता और प्रभावशीलता टिकाऊ पद्धति से प्राप्त की जा सकती है।

भारत ने विकासशील देशों हेतु सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने के लिए से आवश्यक 5.8 ट्रिलियन डॉलर की राशि की मांग की है। एमडीबी इस राशि का केवल कुछ अंश ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए निजी पूंजी और संस्थागत निवेश की आवश्यकता है। निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विवेकपूर्ण विनियमन के साथ–साथ वित्तीय साधनों में नवाचार की आवश्यकता है।

भारत की जी–20 की अध्यक्षता, जी–20 के इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुनिया में व्याप्त भू–राजनीतिक तनावों के बावजूद, भारत घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति हासिल करने में सक्षम रहा। भारत ने अफ्री. की संघ को जी–20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना सक्षम बनाया, जिससे न केवल वैश्विक आबादी के प्रति. निधित्व में वृद्धि होती है, बल्कि निष्पक्ष और समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। भारत ने खोखले वादे करने के बजाय सदैव कदम उठाने और कार्यान्वयन करने का आह्वान किया है। इसने 59 कार्रवाई योग्य बिंदु प्रस्तावित किए हैं जो घोषणा पत्र से जाहिर है।

ारत ने देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके और इस तरह इसको एक सहभागितापूर्ण कार्यक्रम बनाते हुए जी–20 सदस्यों का मार्गदर्शन भी किया है। इस प्रकार, भारत की अध्यक्षता न केवल आशा का अग्रदूत बन चुकी है, बल्कि कार्रवाइयों का कार्यपद्धति भी बन चुकी है। ■

Continued from page 11...

परिकेसिट, ग्लोबल सॉल्यूशन इनिशिएटिव, जर्मनी के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. डेनिस स्नोवर, इंटरनेशनल रिलेशंस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रोसारियो, अर्जेंटीना में प्रोफेसर डॉ ग्लेडिस लेविचनी, केएपीएसएआरसी, सऊदी अरब में सीनियर एसोसिएट, अर्थशास्त्री डॉ. मा. जिद अल्मोजियानी, ग्रैंड पेरिस एलायंस फॉर मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट, फ्रांस के सह–संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. निकोलस जे. ए. बुचौड, केएपीएसएआरसी, सऊदी अरब में रिसर्च फेलो डॉ नौरा मंसूरी, एशिया–पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ एलर्जी अस्थमा और क्लिनिकल इम्यूनालॉजी की अध्यक्ष डॉ. रूबी पवनकर, जीआईजेड, जर्मनी, ज्ञान साझेदारी के लिए नीतिगत सलाहकार डॉ. होल्गर कुहले, आरआईएस में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रियदर्शी दाश और आरआईएस में सहायक प्रोफेसर डॉ बीना पांडे शामिल थे। सह–अध्यक्षों ने आगामी विभिन्न साइड इवेंट, खंडों, और अकादमिक नोट्स के बारे में भी चर्चा की। ■

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- भोपाल में 2 जुलाई 2023 को भारतीय सामाजिक उत्तरदायित्व नेटवर्क द्वारा आयोजित सेवा एवं सुशासन पर सरकारी पहल से संबंधित सी–20 सेवा शिखर सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित किया।
- 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के साथ साझेदारी से मानव विकास संस्थान (आईएचडी), नई दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और सदर्न सेंटर ऑफ इनइक्वालिटी स्टडीज, डब्ल्यूटीएफ यूनिवर्सिटी, जोहान्सबर्ग द्वारा आयोजित नई प्रौद्योगिकियों और ग्लोबल साउथ में कार्य के भविष्य पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'नई प्रौद्योगिकियां और उभरते श्रम बाजारः वैश्विक परिप्रेक्ष्य' पर पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की।
- 18 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश ग्रामीण संवाद 2023 में ग्रामीण पुनर्जागरण के लिए आरंभिक विचारों पर उद्घाटन सत्र में पैनलिस्ट। (ऑनलाइन)
- आयुष मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2023 को सहभागिता समूहों के साथ आयोजित सभा में थिंक–20 में पारंपरिक चिकित्सा पर सत्र में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आईडी. आरसी और जीडीएन के साथ 28 जुलाई 2023 को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर आयोजित सम्मेलन में प्रौद्योगिकी, नीति, नौकरियों पर सत्र की अध्यक्षता की।
- मैसूरु में एसएआईआईए द्वारा 31 जुलाई 2023 को आयोजित थिंक–20 अफ्रीकन स्टैंडिंग ग्रुप (टी–20 एएसजी) बैठक में जी–20 की भारत की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रस्तुति दी।
- यूएनएड्स द्वारा 31 जुलाई 2023 को एसडीजी–3 में तेजी लाने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिकाः वैश्विक स्वास्थ्य, कोविड–19 और एचआईवी–एड्स में जी–20 गैर–डीएसी देशों का योगदान विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में उद्घाटन भाषण दिया।
- मैसूरु में एसएआईआईए द्वारा 2 अगस्त 2023 को अनुकूलन एवं वैश्विक वित्तीय संरचना पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट।
- मैसूरु में 2 अगस्त 2023 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा बिहा. इंड द सीन्सः मेकिंग ऑफ द इंडियन जी–20 विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली में 10 अगस्त 2023 को सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस (सीआरबी) और भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजित मिशन लाइफ के प्रभावी कार्यान्वयन की ओरः उपभोक्ता कर्तव्यों से उपभोक्ता अधिकारों तक सम्मेलन में भाषण दिया।
- भारतीय दूतावास, मैक्सिको द्वारा 10 अगस्त 2023 को आयोजित इंडिया–मैक्सिको रिसर्च कंसोर्टियम (आईएमआ. रसी) में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर सत्र में पैनलिस्ट। (ऑनलाइन)
- गांधीनगर, गुजरात में 18 अगस्त 2023 को डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडि. सिन सेंटर द्वारा भारत सरकार के साथ सह–आयोजित डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलनः सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण में नीति, कानूनी और नियामक परिदृश्य पर सत्र में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 25 अगस्त 2023 को कोर्बर–स्टिफ्टंग और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित म्यूनिख यंग लीडर्स एलुमनाई की वार्षिक बैठक में रिवॉल्विंग अराउंड इंडियाज जी–20 प्रेसीडेंसी : वसुधैव कुटुंबकम – विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ मल्टीलैटरा. लिस्म सत्र में पैनलिस्ट।
- दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 5 सितंबर 2023 को सतत विकास लक्ष्यों के लिए भारत के जी–20 विजन, कानूनी और नीतिगत नेतृत्व पर आयोजित संगोष्ठी में सम्मानित अतिथि।
- जीआईजेड द्वारा 6 सितंबर 2023 को 'जीआईजेड के लिए भारत के वैश्विक प्रभाव और निहितार्थ' पर ऑनलाइन आयोजित गोलमेज सम्मेलन में पैनलिस्ट।
- मैनेजिंग ग्लोबल गवर्नेंस ग्लोबल नेटवर्क कॉन्फ्रेंस (एमजीसी नेटवर्क) द्वारा 27 सितंबर 2023 को आयोजित एमजीजी ग्लोबल नेटवर्क कॉन्फ्रेंस 2023 में बदलती वैश्विक व्यवस्था में दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर सत्र में पैनलिस्ट।

श्री जी. ए. तड़स

सलाहकार

- टी–20, एनसीडी अलायंस और एमएसडी द्वारा 6 जुलाई 2023 को 'लगभग 75 प्रतिशत वैश्विक मौतें गैर–संचारी रोगों के कारण होती हैं – जी–20 कैसे मदद कर सकता है?' विषय पर आयोजित विशेषज्ञ गोलमेज सम्मेलन (वर्चुअल इवेंट) में भाग लिया।
- मैसूरु में 31 जुलाई– 2 अगस्त 2023 को 'एसडीजी को बचानाः 2030 के एजेंडे के लिए नए मार्ग तलाशना' विषय पर आयो. जित टी–20 शिखर सम्मेलन भाग लिया।
- आरआईएस और आईएफपीआरआई द्वारा नई दिल्ली में 17 अगस्त 2023 को 'बिम्सटेक में कृषि व्यापारः नए अवसर और आगे की राह' विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में 'व्यापार और निवेश की सहायता हेतु कृषि वित्त' में भाग लिया।
- आरआईएस और फोर्थ सेक्टर ग्रुप (एफएसजी), नई दिल्ली, द्वारा 9 सितंबर 2023 को आयोजित लाइफ अर्थव्यवस्था रणनीति गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- आरआईएस, फोर्थ सेक्टर ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा 9 सितंबर 2023 को आयोजित लाइफ अर्थव्यवस्था रणनीति गोलमेज सम्मेलन में ग्लोबल अलायंस फॉर लाइफ इकोनॉमीज रिसर्च एंड इनोवेशन (जीएएलईआरआई) का गठनः गतिविधियों, संरचना, फंडिंग, प्रशासन का दायरा, पर अवधारणा नोट दिया।

डॉ. पंकज वशिष्ठ

एसोसिएट प्रोफेसर

- इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय द्वारा 5–6 सितंबर 2023 को आयोजित "आसियान हिंद–प्रशांत फोरम" में भाग लिया।
- पुणे में 1 सितंबर 2023 को 'भारत में एमएसएमई डिजिटलीकरणः चुनौतियां और आगे की राह' विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

डॉ भास्कर बालाकृष्णन

विजिटिंग फेलो

- आईएमपीआरआई, नई दिल्ली द्वारा में 29 सितंबर को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अंतर्गत "विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति" विषय पर व्याख्यान दिया।
- आईसीडब्ल्यूए द्वारा माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी की भागीदारी सहित 27 सितंबर 2023 को "भारत–क्यूबा संबंध" पर आयोजित पैनल चर्चा में चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया।

डॉ पी के आनंद

विजिटिंग फेलो

- जी–20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में प्रेसीडेंसी नोट ऑफ डिस्कशन्स के लिए इनपुट तैयार किए।
- यूएनडीपी द्वारा 10 जुलाई 2023 को "स्थानीय सरकारें किस प्रकार एसडीजी का उपयोग पुनर्विचार के लिए कर रही हैं?" शीर्षक से आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- यूएन हैबिटेट द्वारा 12 जुलाई 2023 को आयोजित "एसआईसीए क्षेत्र (एचएलपीएफ 2023 साइड इवेंट) में नए शहरी एजेंडा (एनयूए) के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना और एसडीजी 11 को प्राप्त करना" में भाग लिया।
- यूएन वॉटर द्वारा 17 जुलाई 2023 को आयोजित बैठक "एसडीजी 6 और जल कार्रवाई एजेंडा" में भाग लिया।
- स्टेटिस्टा द्वारा 20 जुलाई 2023 को आयोजित "द पावर ऑफ जेन जी : फ्रॉम रेडिकलिज्म टू सस्टेनेबल कंजम्पशन" में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 20 जुलाई 2023 को आयोजित "अनियमित प्रवासन और खाद्य सुरक्षाः पश्चिम अफ्रीका के दृष्टिकोण" में भाग लिया।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, आईईपीएफए और एनसीएईआर द्वारा 17 अगस्त, 2023 को आयोजित "निवेशक जागरूकता और सुरक्षा वेबिनार" में भाग लिया।
- ईआरआईए द्वारा 23 अगस्त 2023 को आयोजित "शहरी अनुकूलन के लिए एसएमई को सशक्त बनाना" में भाग लिया।
- आईएसआईडी द्वारा 28 अगस्त 2023 को आयोजित "भारतीय शहरों का डिजिटलीकरणः क्षेत्रीय विविधताएं" विषय पर अनुसंधान संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 7 सितंबर 2023 को खाद्य और कृषि बाजारों की समझ बनाने पर आईएफपीआरआई–एएमआईएस श्रृंखला की चौथी संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 1 सितंबर 2023 को आयोजित "खाद्य सुरक्षा रुझान और अनुकूलन–निर्माण प्राथमिकताएं" में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 26 सितंबर 2023 को "बेहतर प्रारंभिक चेतावनी के मार्गदर्शन सहित प्रत्याशित कार्रवाई सुगम बनाना" पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- एडीबी द्वारा 28 सितंबर 2023 को आयोजित "अनलॉकिंग कैपिटल फॉर सस्टेनेबिलिटी" में भाग लिया।

नवीनतम प्रकाशन

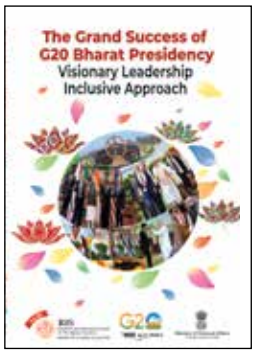

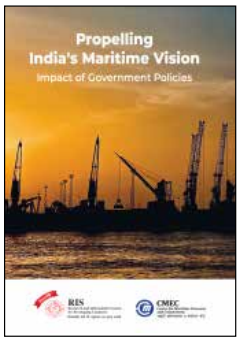

पुस्तकें/रिपोर्टें

☐ **द ग्रैंड सक्सेस ऑफ जी–20 भारत प्रेसीडेंसी**, आरआईएस, नई दिल्ली, 2023

☐ **जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स**, आरआईएस, नई दिल्ली, 2023

☐ **प्रपेलिंग इंडियाज मैरीटाइम विजन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज**, आरआईएस–सीएमईसी, नई दिल्ली, 2023

पत्रिकाएं

☐ **डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू**, खंड–16 संख्या–3, जुलाई–सितम्बर, 2023

☐ **जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन**, खंड–5 संख्या–2, सितम्बर, 2023

आरआईएस चर्चा पत्र

284: असेसिंग इंडिया–वियतनाम मैरीटाइम ट्रेड: ऐन एम्पिरिकल एक्सप्लोरेशन बाइ प्रबीर डे एंड तुहिनसुभ्रा गिरी

283: ट्रेडिशनल मेडिसिन इन सार्क : अ रीजनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बाइ नम्रता पाठक

मेकांग गंगा नीतिगत सारांश

संख्या 12, जनवरी, 2023

एआईसी कॉमेंट्रीज

- संख्या 42: पोटेंशियल ऑफ आसियान–इंडिया पार्टनरशिप इन मैनेजिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, अगस्त 2023
- संख्या 41: फॉर्टी सेकंड आसियान समिट: आउटकम्स एंड फ्यूचर आउटलुक, जुलाई 2023

आरआईएस संकाय द्वारा बाहरी प्रकाशनों में योगदान

आनंद, पी.के., और कुमार, के. (2023)। "गोइंग बियोंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी): वैल्यूइंग वेलबीइंग"। टी–20 पॉलिसी ब्रीफ. टास्कफोर्स 3. टी–20 इंडिया सचिवालय।

आनंद, पी.के., और कुमार, के. (2023)। " फाइनेंसिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल एग्रीफूड सिस्टम्स"। टी–20 पॉलिसी ब्रीफ. टास्कफोर्स 6. टी–20 भारत सचिवालय।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. 'सॉलिडेरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल साउथः इंडियन जी–20 इनिशिएटिव्स'; शर्मा, एन. श्रीवास्तव, ए.; मिश्रा, विवेक कुमार और ठाकरे, भूषण (संपा.) सॉलिडेरिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी : कॉमन कन्सर्न्स फॉर ग्लोबल कॉमन्स में डब्ल्यूओएसवाई फाउंडेशनः नई दिल्ली

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "रिमार्क्स" महावर, एन., और भट्टाचार्जी, डी., (संपा) इंडियाज डेवलेपमेंट पार्टनरशिपः एक्सपेंडिंग विस्टाज में, आईसीडब्ल्यूए। पृष्ठ 13–19.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "सम यूनिक फैसिट्स ऑफ इंडियाज जी–20 प्रेसीडेंसी" किर्टन, जॉन.; और कोच, मेडलिन, (संपा.) इंडिया द न्यू दिल्ली समिट, में। जीटी मीडिया ग्रुप लिमिटेडः यूके। पृष्ठ 42–43

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "इंडोनेशिया एंड इंडियन जी–20 प्रेसीडेंसीज इन पर्सपेक्टिव" ईस्ट एशिया फोरम क्वार्टरली, खंड 15 संख्या 3 जुलाई–सितंबर 2023. पृष्ठ 17–21.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. भारत–पश्चिम एशिया–यूरोपीय आर्थिक गलियारा। गतिशक्ति का अन्तरराष्ट्रीयकरण। अमर उजाला, सितंबर। (हिंदी में)।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. क्लोजर लिंक्स, फास्टर ग्रोथः अ न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर डेक्कन हेराल्ड, 17 सितम्बर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. जी–20 समिट इंडियाः इंडियन इथोज एंड वैल्यूज फॉर ग्लोबल सॉल्यूशन्स। ऑर्गेनाइज़र, 05 सितम्बर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. डेटा बियोंड सर्वेः स्टैटिस्टिकल सिस्टम रिक्वॉयर्स रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टेट–ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज इंडियन एक्सप्रेस, जुलाई।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर भारतः कन्ट्राडिक्शन्स, कॉम्प्लीमेंटरीज एंड द वे फॉरवर्ड", महाजन, अश्विनी (संपादित) आत्मनिर्भरः अ स्वदेशी पैराडाइम में रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पृष्ठ 1–17.

डे, पी. 2023. "अनलॉकिंग द जीवीसी पोटेंशिल्स इन इंडियाः रोल ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन"। टी बी चटर्जी, ए घोष और पी रॉय (संपा.) रिस्क एंड रेजिलिएंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज : एसैज इन ऑनर ऑफ प्रोफेसर अजित्वा रायचौधुरी, स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर।

डे,पी. और अंबुमोझी, वी., 2023. क्रॉस–बॉर्डर एनर्जी ट्रेड एंड डेवलेपमेंट ऑफ बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स (बीईजेड) इन नॉर्थईस्ट इंडियाः टुअर्ड ऐन इंटीग्रेटेड रीजनल प्रोग्राम। अंबुमोझी, वी. और सिंह, के.बी. (संपा.), क्रॉस–बॉर्डर इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स (पृष्ठ 56–96) में। रूटलेज, नई दिल्ली।

डे,पी. 2023 "म्यांमार्ज इंटीग्रेशन विद् द वर्ल्डः इमर्जिंग ट्रेन्ड्स एंड वे फॉरवर्ड ", आनंद, वी. और वशिष्ठ, सी (संपा.), रीविज़िटिंग म्यांमारः प्रेजेंट थ्रू द पास्ट, में, वीआईएफ और पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली।

डे, पी. 2023 (अगस्त)। "व्हॉट केन वी एक्सपेक्ट द ट्वेंटिएथ आसियान–इंडिया समिट टू डिलिवर?", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड 1, संख्या 7

डे, पी. 2023 (6 सितंबर)। ट्वेंटिएथ आसियान–इंडिया समिटः एक्सपेक्टेशन्स एंड चैलेंजिस", इकोनॉमिक टाइम्स।

डे, पी. 2023. "ट्वेंटिएथ आसियान–इंडिया समिटः की टेकअवेज"। ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड1, संख्या 8.

डे, पी. 2023. "इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसीः द पावर ऑफ प्रोग्रेस", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड1, संख्या 6.

डे, प्रबीर (2023) "इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसीः द पावर ऑफ प्रोग्रेस", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड1, संख्या 6, जुलाई 2023

तड़स, ए.जी. 2023. 'चूजिंग लाइफ इन जी–20 इंडिया'। किर्टन जे एंड कोच एम (संपा.) में, जी–7 इंडियाः 2023 न्यू दिल्ली समिट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पृष्ठ. 58–59.

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर IV-B, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी मार्ग, नई दिल्ली–110 003, भारत। दूरभाष 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ईमेलः dgoffice@ris.org.in
वेबसाइटः www.ris.org.in

Follow us on:

www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबन्ध सम्पादक : तीश मल्होत्रा